

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता नयिम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार ने **समान नागरिक संहिता (UCC)** के नयिमों को मंजूरी दे दी है और **जनवरी 2025** के अंत तक कानून के लिये राजपत्र अधिसूचना जारी करने की योजना है, जिससे इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्य बटु

- **UCC के प्रमुख प्रावधान:**
 - फरवरी 2024 में उत्तराखण्ड वधिनसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता (UCC) आदविसी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखती है।
 - यह हलाला, इददत और तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतबिंध लगाता है, जो **मुसलमि परसनल लॉ** के तहत प्रथाएँ हैं।
 - यह सुनश्चिति करता है कि महिलाओं को संपत्त और उत्तराधकार के मामलों में **समान अधकार प्राप्त हों**।
 - संहिता में वविह और तलाक के पंजीकरण को अनविर्य बनाया गया है, जसिका अनुपालन न करने पर सरकारी लाभों से वंचति होना पड़ेगा।
 - अपंजीकृत लवि-इन संबंधों के लिये कड़े प्रावधान मौजूद हैं, हालाँकि ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाता है।
- **कार्यान्वयन उपाय:**
 - सरकार ने वविह, तलाक, उत्तराधकार अधकार, लवि-इन रलेशनशपि और लवि-इन रलेशनशपि की समाप्त के पंजीकरण के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापति कया है।
 - नागरिक अपने डेटा और आवेदन की स्थतिको मोबाइल फोन या घर से देख सकते हैं।
 - सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) को ऑनलाइन पंजीकरण के लिये अधकृत कया गया है।
 - इंटरनेट सुवधि से वंचति दूरदराज के क्षेत्रों में CSC एजेंट घर-घर जाकर पंजीकरण सेवाएँ प्रदान करेंगे।
 - सरलता और सुवधि के लिये ईमेल और एसएमएस के माध्यम से आधार-आधारति पंजीकरण और ट्रैकगि की शुरुआत की गई है।
 - ऑनलाइन शकियायत पंजीकरण तंत्र भी स्थापति कया गया है।



UNIFORM CIVIL CODE

All sections of the society irrespective of their religion shall be treated equally according to a National Civil Code - the Uniform Civil Code.

THEY COVER AREAS LIKE



Marriage



Divorce



Maintenance



Inheritance



Adoption



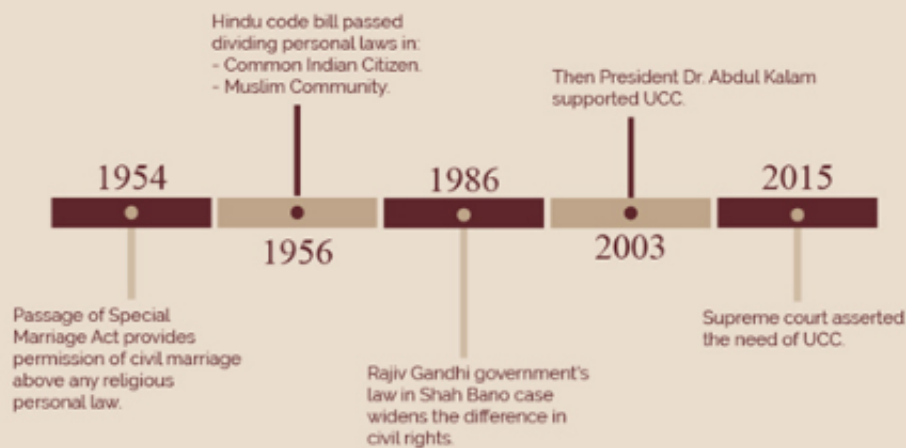
Succession of Property

It is based on the premise that there is necessarily no connection between religion and personal law in a civilized society.

"UCC refers to a common set of laws governing civil rights of every citizen."

Article 44 of Directive Principles sets duty of state for implementing UCC.

TIMELINE



The dialogue for UCC was started by the Law Commission in the year 2016